दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

दिसंबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **5**

- 6 चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी 5
- एमएसएमई विभाग और वॉलमार्ट एवं फ्लिपकार्ट के बीच एमओयू 5
- भू-अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन प्राप्त होगी 6
- तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप में श्वेता नेमा ने जीते एक साथ चार पदक 6
- साहित्य अकादमी के वर्ष 2017 के शेष कृति पुरस्कार घोषित 7
- 5वाँ टी-20 मास्टर कप (वेटरन) का शुभारंभ 7
- महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन कराने की मिली अनुमति 8
- दुबई एक्सपो-2020 8
- ग्राम पंचायत बरोदियाकलां बनी नगर परिषद 9
- तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव 9
- टंट्या भील बलिदान दिवस 10
- नवीन आदर्श ग्राम योजना 10
- राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कार्यशाला गोवा में संपन्न 11
- 75वाँ होमगार्डस् स्थापना दिवस समारोह 11
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक 12

नोट :

- सशस्त्र झंडा दिवस 13
- हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता लेगा मध्य प्रदेश एच.एस.व्ही.एन 13
- प्रदेश की पहली सोलर सिटी साँची में लगेगा 6 हज़ार किलोवाट का सोलर सिस्टम 14
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टास्क फोर्स की बैठक 14
- स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021 15
- केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को मिली मंज़ूरी 15
- दुलार किट और कंपोस्टेबल बैग कार्यक्रम का शुभारंभ 16
- डाक सेवा अवार्ड-2021 17
- भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू 17
- राज्य को मिलीं 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन 18
- राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित 18
- भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2021 19
- 'ड्रोन मेला' 19
- ई-व्हीकल्स रोड-शो 20
- मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महँगाई राहत की दर में वृद्धि 20
- EDII को उद्यमिता में 'उत्कृष्टता केंद्र'का दर्जा मिला 21
- जबलपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिये 21 एकड़ भूमि आवंटित 22
- टीकाकरण महाभियान-10 22
- मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस समारोह 23
- 'वास्तुकला रचना प्रतियोगिता' का शुभारंभ 23

नोट :

- 'इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कांक्लेव-2021' अवार्ड 24
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित 24
- चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव-2022 मोबाइल एप 25
- विक्रमोत्सव-2021 25
- देव श्रीमाली की पुस्तक 'बिछड़े कई बारी बारी' का विमोचन 26
- 'निर्झरणी महोत्सव' 26
- खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग के पहले चरण का समापन 27
- राज्यपाल ने अरबिंदो विश्वविद्यालय में केंद्रीय नैदानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया 27
- मुख्यमंत्री ने किया '1857 की क्रांति और नीमच' पुस्तक का विमोचन 27
- 'तानसेन समारोह' 28
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 भोपाल में होंगे 28
- जैव-विविधता संरक्षण के लिये 9 ज़िलों में विकसित होंगे आयुष वन 29
- सुशासन सूचकांक, 2021 में मध्य प्रदेश 29
- पँश्री डॉ. कपिल तिवारी ने किया हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ 30
- नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश 30
- उज्जैन में खुलेगा आईआईटी इंदौर का सेटेलाइट कैंपस 31
- विभिन्न निगम, मंडल, बोर्ड तथा प्राधिकरण के अध्यक्षों को तथा कैबिनेट मंत्री का दर्जा और उपाध्यक्षों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा 31
- उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को मिला नैक से सर्वोच्च ए+ ग्रेड 32
- पंचायतों का फिर से होगा परिसीमन 32

नोट :

मध्य प्रदेश

6 चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

- 30 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक। प्रदेश में 1547 करोड़ 45 लाख रुपए से 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य की मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इसमें मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच तथा मंदसौर में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिये क्रमश: राशि रुपए 249.63 करोड़, 258.07 करोड़, 256.83 करोड़, 256.55 करोड़, 255.78 करोड़ तथा 270.59 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
- इसके साथ ही मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) को वर्तमान में प्रशासन अकादमी से पृथक् कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- सीमेट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक योजना एवं शैक्षणिक प्रबंधकीय क्षमता का विकास तथा इसके विकेंद्रीकरण के संबंध में उचित प्रक्रिया का निर्धारण एवं विकास करना है। इसके लिये व्यावसायिक दक्षता के विकास, शैक्षिक प्रबंधन में पाठ्यक्रमों का संचालन, शिक्षा से जुड़े अधिकारियों की क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण वातावरण के निर्माण में सहयोग करना शामिल है।
- सीमेट में स्कूल शिक्षा विभाग एवं स्कूल प्रबंधन से जुड़े जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

एमएसएमई विभाग और वॉलमार्ट एवं फ्लिपकार्ट के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों ?

- 30 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे हाल (मिंटो हाल) में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सुनियोजित नीति के तहत एमएसएमई विभाग ने मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक नवउद्यमियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का बनाने और प्रतिस्पर्द्धा तथा मार्केटिंग चेन बनाने के लिये वॉलमार्ट एवं फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा की उपस्थिति में विभाग के सचिव पी. नरहरि और वॉलमार्ट के डायरेक्टर जोसफ जूलियन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर तथा आदान-प्रदान हुआ। फ्लिपकार्ट के रीजनल हेड डी.पी. वानकानी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
- एमएसएमई मंत्री ने कहा कि नवउद्यमियों को इस एमओयू से संबल मिलेगा। यह एमओयू रिटेल और होलसेल मार्केटिंग के साथ ही उत्पाद की पैकिंग, प्रतिस्पर्द्धा, गुणवत्ता और लागत को उपभोक्ता के हिसाब से सुनिश्चित करने के लिये नवउद्यमियों को प्रशिक्षित भी करेगा।
- आयुक्त और एमएसएमई सचिव पी. नरहरि ने कहा कि इस एमओयू से मध्य प्रदेश के उद्यमियों के उत्पादों के लिये देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के बीच नए द्वार खुलेंगे। इस एमओयू में नए-नए मॉड्यूल, उद्योगों के विकास, प्रशिक्षण, सेमीनार आदि को भी समाहित किया गया है। राज्य के नवउद्यमी इससे लाभांवित होंगे।

नोट :

- वॉलमार्ट वृद्धि के डायरेक्टर जोसफ जूलियन ने कहा कि वे उद्योगों के विकास, बाज़ार और प्रतिस्पर्द्धा के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे।
- फ्लिपकार्ट के रीजनल हेड डी.पी. वेलीकान ने कहा कि मध्य प्रदेश की उद्योग मित्र नीतियाँ उनके नेटवर्क के अनुकूल हैं। उन्होंने कोरोनाकाल में राज्य शासन द्वारा उद्योगों को दी गई सहूलियतों का उल्लेख करते हुए कहा कि फ्लिपकार्ट एमएसएमई सेक्टर को आगे ले जाने का हर संभव प्रयास करेगा।

भू-अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन प्राप्त होगी

चर्चा में क्यों ?

- 1 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने का सुगम और आसान तरीका बनाने के निर्देशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने भू-अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- भू-स्वामी अपनी भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिये आईटी सेंटर, एम.पी. ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र, कियोस्क सेंटर और शासन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- ऑनलाइन मिलने वाली भू-अधिकार पुस्तिका सामान्यत: दो पृष्ठों की होगी। इसके लिये शासन द्वारा 45 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।
- किसी विशेष प्रकरण में पुस्तिका यदि अधिक पृष्ठों की है, तो प्रत्येक पृष्ठ के लिये 15 रुपए अतिरिक्त देय होंगे।
- पूर्व में प्राप्त की गई भू-अधिकार पुस्तिका यथावत उपयोग में ली जा सकेगी। राजस्व विभाग द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका प्रदाय करने के लिये समय-सीमा लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित की गई है।
- भूलेख पोर्टल से भू-अधिकार पुस्तिका की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड कर आवेदक को निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय की जाएगी।
- ऑनलाइन भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिये कृषक/आवेदक को अपना आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, पटवारी हलका और सेक्टर क्रमांक आदि अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
- भू-अधिकार पुस्तिका का आवेदन अमान्य किये जाने अथवा समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर आवेदक को अपील करने का अधिकार होगा।
- आवेदक प्रथम अपील 30 दिवस और द्वितीय अपील 60 दिवस में प्रस्तुत कर सकेगा। दोनों ही अपील निराकरण करने की समय-सीमा 15 दिवस निर्धारित की गई है।

तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप में श्वेता नेमा ने जीते एक साथ चार पदक

चर्चा में क्यों ?

- 27-30 नवंबर तक वाराणसी स्थित डॉ. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल स्टेडियम में एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश टीम की प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा लेने वाली बौद्ध-भारतीय ज्ञानोदय अध्ययन विश्वविद्यालय की पीएचडी शोधकर्त्ता श्वेता नेमा ने एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक जीते।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित इस मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में श्वेता ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण, रेस वॉक में रजत और 400×4 रिले में कांस्य तथा 100×4 रिले दौड़ में दूसरा कांस्य पदक जीता।
- इस 4 दिवसीय तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश भर से केवल 30 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागियों ने ही मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया।

नोट :

- गौरतलब है कि श्वेता विश्वविद्यालय में योग और आयुर्वेद विभाग में पीएचडी शोधकर्त्ता हैं। श्वेता नेमा ने हाल ही में SATI कॉलेज, विदिशा में कछुए की मुद्रा में योग करने का गिनीज़ रिकॉर्ड बनाया था। श्वेता विदिशा और रायसेन के लोगों को मुफ्त योगासन का प्रशिक्षण देती हैं।

साहित्य अकादमी के वर्ष 2017 के शेष कृति पुरस्कार घोषित

चर्चा में क्यों ?

- 2 दिसंबर, 2021 को संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद ने कैलेंडर वर्ष 2017 के शेष 6 अखिल भारतीय और 6 प्रादेशिक कृति पुरस्कारों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय पुरस्कार में एक लाख रुपए और प्रादेशिक पुरस्कार में 51 हज़ार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है।
- अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे ने बताया कि छ: अखिल भारतीय पुरस्कारों में 'आत्मकथा-जीवन' श्रेणी में 'अखिल भारतीय विष्णु प्रभाकर पुरस्कार' वाराणसी के संदीप देव को रचना 'हमारे श्री गुरु जी' के लिये, 'संस्मरण' श्रेणी में 'अखिल भारतीय निर्मल वर्मा पुरस्कार' खंडवा के संतोष तिवारी को उनकी रचना 'रिश्ते मन से मन के' के लिये, 'रेखाचित्र' श्रेणी में 'अखिल भारतीय महादेवी वर्मा पुरस्कार' दिल्ली के संजय सिन्हा को 'शुक्रिया' के लिये, 'यात्रा वृत्तांत' श्रेणी में 'अखिल भारतीय प्रो. विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार' गाज़ियाबाद के विनोद बब्बर को 'भगीरथ के देश में' के लिये, 'अनुवाद' श्रेणी में 'अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार' दिल्ली के अमरनाथ श्रीवास्तव को 'कारगिल के परमवीर' के लिये और 'फेसबुक/ब्लॉग/नेट' श्रेणी में 'अखिल भारतीय नारद मुनि पुरस्कार' उज्जैन के सुरेश चिपलूनकर को उनके पेज: 'ब्लॉक/फेसबुक' के लिये दिया गया है।
- शेष छ: प्रादेशिक पुरस्कारों में 'संवाद, पटकथा लेखन' श्रेणी में 'प्रादेशिक नरेश मेहता पुरस्कार'भोपाल के अयोध्या प्रसाद सोनी को उनकी रचना 'खाली पिंजरा और हिंदुस्तान का पानी'के लिये, 'लघुकथा'श्रेणी में 'प्रादेशिक जैनेन्द्र कुमार 'जैन' पुरस्कार' भोपाल के घनश्याम मैथिल 'अमृत'को उनकी रचना 'एक लोहार की' के लिये, 'एकांकी' श्रेणी में 'प्रादेशिक सेठ गोविंद दास पुरस्कार' भोपाल के अरविंद शर्मा को 'सपना सच हो गया' के लिये, 'व्यंग्य' श्रेणी में 'प्रादेशिक शरद जोशी पुरस्कार'उज्जैन के मुकेश जोशी को 'ऑल इज वेल' के लिये, 'गीत'श्रेणी में 'प्रादेशिक वीरेंद्र मिश्र पुरस्कार'सतना के छोटेलाल पांडेय को 'वीरव्रती आज़ाद'और 'गजल'श्रेणी में 'प्रादेशिक दुष्यंत कुमार पुरस्कार' ग्वालियर के मनीष जैन 'रौशन' को उनकी रचना 'रंग खुशबू के'के लिये दिया गया है।

5वाँ टी-20 मास्टर कप (वेटरन) का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 2 दिसंबर, 2021 को गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ओल्ड कैम्पियन ग्राउंड में बल्ला चलाकर 5वें टी-20 मास्टर कप (वेटरन) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके पूर्व उन्होंने उद्घाटन मैच की टीमों- 'मीडिया मास्टर्स' और 'सेकेंड इनिंग मास्टर्स' के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।
- स्पोर्ट्स क्लब ऑफ भोपाल समिति संरक्षक राहुल कोठारी ने बताया कि समिति द्वारा पाँचवीं बार टी-20 मास्टर्स कप (वेटरन) और सीनियर डिवीज़न इंटर क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ भोपाल और भोपाल क्रिकेट अकादमी के संयुक्त तत्वावधान किया जा रहा है।
- विगत 2 वर्षों से प्रतियोगिता कोविड-19 महामारी के कारण नहीं कराई जा सकी। इस बार प्रतियोगिता में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता लीग आधारित आयोजित की गई है। इसमें सभी खिलाड़ी कलरफुल ड्रेस में सफेद लेदर बॉल से खेलेंगे।

नोट :

- आयोजन सचिव योगेंद्र व्यास ने बताया कि प्रतियोगिता में बेस्ट बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, विकेट-कीपर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया जाएगा।

महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन कराने की मिली अनुमति

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने पहली बार किसी महिला को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दी है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस महिला आरक्षक ने पुरुष बनने के लिये लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति मांगी थी। जिन्हें पुलिस महानिदेशक ने लिंग परिवर्तन करवाने की अनुमति दी है।
- राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों ने इस बात की पुष्टि की है कि महिला आरक्षक को बचपन से ही जेंडर आइडेंटिटी संबंधी डिसऑर्डर रहा है।
- महिला आरक्षक ने अपने ज़िले में पुरुषों की तरह पुलिस के काम किये हैं। साथ ही विधिवत आवेदन दिया व शपथ-पत्र पेश किया।
- भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में लिंग बदलने की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। इसके बाद ही आवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था। पुलिस मुख्यालय ने इस आवेदन पर गृह विभाग से अनुमति मांगी थी।
- विधि विभाग ने गृह विभाग को दिये परामर्श में कहा था कि भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिये बिना अपने लिंग का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद अनिता को लिंग परिवर्तन की अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं है।
- उल्लेखनीय है कि पाँच वर्ष पहले बीड की 29 वर्षीय महिला कॉन्स्टेबल ललिता साल्वे ने लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी थी। वह देश का पहला केस था। तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करने के बाद वह ललिता साल्वे से ललित साल्वे बन गई थीं।
- जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर/जेंडर डिस्फोरिया वह स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका प्राकृतिक लिंग उसकी लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता।

दुबई एक्सपो-2020

चर्चा में क्यों ?

- 3-9 दिसंबर, 2021 तक दुबई एक्सपो-2020 में मध्य प्रदेश 'राज्य सप्ताह' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगाँव ने 'मध्य प्रदेश मंडप' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस 'राज्य सप्ताह' में विभिन्न उद्योग-विशिष्ट विशेषज्ञ सत्र, गोलमेज चर्चा के साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होंगे।
- दुबई एक्सपो में मध्य प्रदेश सप्ताह में राज्य के लिये व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा करने और वस्त्र निर्माण, ऑटोमोबाइल, ईवी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सहित प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिये विभिन्न बैठकें होंगी।
- एक्सपो के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगाँव की अध्यक्षता में राज्य का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और प्रदान करने के उद्देश्य से नए निवेश, नई प्रौद्योगिकियों, राज्य में लाभकारी रोज़गार प्रदाय करने हेतु नई परियोजनाओं को लाने के लिये उद्योग घरानों और उद्योग संघों के साथ बातचीत करेगा।
- मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि-मंडल संयुक्त अरब अमीरात सरकार की वार्षिक निवेश बैठक (एआईएम) के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेगा, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिये दुनिया का अग्रणी मंच है।

नोट :

- साथ ही मार्च 2022 में एआईएम, दुबई में होने वाली बैठक के लिये हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक से निमंत्रण प्राप्त किया।
- प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स, शारजाह चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीआईओसीसीआई) से भी मिलेंगे। इसके अलावा दुबई, शारजाह और अबू धाबी के विभिन्न प्रमुख कॉर्पोरेट्स के साथ बैठकें करेंगे।

ग्राम पंचायत बरोदियाकलां बनी नगर परिषद

चर्चा में क्यों ?

- 3 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा सागर ज़िले की तहसील मालथौन की ग्राम पंचायत बरोदियाकलां को नगर परिषद बनाया गया। इस संबंध में मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत 7 ग्राम पंचायतों के 22 ग्रामों को मिलाकर बरोदियाकलां को नगर परिषद बनाया गया है।
- इसमें ग्राम पंचायत बरोदियाकलां सहित डबडेरा, बीकोरकलां, दरी, रजवांस, बनखिरिया और उमरई ग्राम पंचायत शामिल की गई हैं।
- बरोदियाकलां क्षेत्र के नागरिकों ने इस उपलब्धि पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह को धन्यवाद दिया।

तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

चर्चा में क्यों ?

- 4 दिसंबर, 2021 को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी।
- आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी।
- यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे हैं, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे।
- मतदान तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, 2022 को होंगे।
- मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण के लिये 6 जनवरी, 2022, द्वितीय चरण के लिये 28 जनवरी, 2022 और तृतीय चरण के लिये 16 फरवरी, 2022 को सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा।
- मतदान केंद्र पर पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी।
- जनपद पंचायत सदस्य एवं ज़िला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से मतगणना प्रथम चरण के लिये 10 जनवरी, 2022 द्वितीय चरण के लिये 1 फरवरी, 2022 और तृतीय चरण के लिये 20 फरवरी, 2022 को सुबह 8 बजे से की जाएगी।
- पंच और सरपंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम चरण के लिये 11 जनवरी, 2022, द्वितीय चरण के लिये 2 फरवरी, 2022 और तृतीय चरण के लिये 21 फरवरी, 20222 को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।
- जनपद पंचायत सदस्य के लिये निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के लिये 22 फरवरी, 2022 को और ज़िला पंचायत सदस्यों के लिये 23 फरवरी, 2022 को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।

नोट :

टंट्या भील बलिदान दिवस

चर्चा में क्यों ?

- 4 दिसंबर, 2021 को राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पातालपानी में क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर अष्टधातु से निर्मित जननायक टंट्या मामा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री चौहान ने जननायक टंट्या मामा के वंशजों और परिजन हीरालाल सिरसाठे, ललिता बाई, दरियाव एवं रेशम बाई वासुदेव, छोगालाल सिरसाठे, रेखा बाई सिरसाठे, राधूलाल और सुंदर बाई का शॉल, श्रीफल और मोतियों की माला पहनाकर सम्मान किया।
- पातालपानी में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नवतीर्थस्थल बनाया जाएगा। यहाँ ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ वीरता की उपासना की जाएगी, जो आने वाली पीढ़ियों को देश-भक्ति की प्रेरणा देगा।
- नवतीर्थस्थल में लाइब्रेरी, व्यू पॉइंट, पाथ-वे के साथ जनजातीय म्यूज़ियम और जननायक टंट्या मामा वाटिका भी बनेगी। साथ ही अब से पातालपानी में हर वर्ष 4 दिसंबर, 2021 को जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर मेला आयोजित होगा।
- टंट्या भील का जन्म सन् 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ (खंडवा ज़िले) की पंधाना तहसील के बड़दाअहीर गांव में भाऊसिंह भील के घर पर हुआ था। कहीं-कहीं पर सन् 1842 में इनके जन्म का उल्लेख भी मिलता है।
- टंट्या भील का वास्तविक नाम तॉतिया था। उन्हें प्यार से टंट्या मामा के नाम से भी बुलाया जाता था। उन्हें सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा आदरपूर्वक 'मामा' कहा जाता था।
- टंट्या भील को कुछ विश्वस्त लोगों के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेजीडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में जबलपुर जेल में रखा गया। सत्र न्यायालय जबलपुर ने उन्हें 19 अक्टूबर, 1889 को फाँसी की सजा सुनाई और फिर 4 दिसंबर, 1889 को फाँसी दी गई।
- फाँसी के पश्चात् इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर पातालपानी रेलवे स्टेशन के नजदीक आसपास के गांवों में विद्रोह भड़कने के डर से चुपचाप रात में उनके शव को उस स्थान, जहाँ पर उनके लकड़ी के पुतले रखे थे, फेंककर अर्थात् रखकर चले गए।
- इस स्थान अर्थात् पातालपानी को आज 'टंट्या भील की समाधि स्थल' के नाम से जाना जाता है।

नवीन आदर्श ग्राम योजना

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजातीय ग्रामों के एकीकृत विकास के लिये मध्य प्रदेश के लिये नवीन आदर्श ग्राम योजना स्वीकृत की है।

प्रमुख बिंदु

- इसमें अधोसंरचना, सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में सुधार, जनजातीय वर्ग के कल्याण और जनप्रतिनिधियों के क्षमता विकास के कार्य होंगे।
- मध्य प्रदेश में इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- योजना में ऐसे ग्राम, जिनकी कम-से-कम 50 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय वर्ग की है और ऐसी जनसंख्या कम-से-कम 500 है, का चयन कर विभिन्न कार्य किये जाएंगे। कुल 7307 ग्रामों का चयन किया गया है।
- इसमें केंद्र से शत-प्रतिशत अनुदान सहायता मिलेगी। प्रथम चरण में 1204 ग्रामों में कार्य होंगे। इन ग्रामों में से प्रदेश में श्रेष्ठ कार्यों के लिये तीन ग्राम चयनित कर 5-5 लाख रुपए के पुरस्कार भी दिये जाएंगे।
- राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिये तीन ग्रामों का चयन होगा, जिन्हें 10-10 लाख रुपए के पुरस्कार दिये जाएंगे।

नोट :

राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कार्यशाला गोवा में संपन्न

चर्चा में क्यों ?

- 5 दिसंबर, 2021 को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2030 तक एक बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के चलते राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये यातायात के साधनों में डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर अधिक-से-अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकल्पों को अपनाया जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिये अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के उपयोग एवं निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रभावी कार्ययोजना बनाकर इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 2030 तक वाहनों की कुल बिक्री में कम-से-कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा गया है।
- मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिये वाहनों के क्रय पर मोटर यान कर एवं पंजीयन शुल्क में छूट दे चुकी है। प्रदेश में विभिन्न वर्गों के 34 हज़ार 500 इलेक्ट्रिक वाहनों पर 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' के तहत लाइफटाइम टैक्स एक फीसदी की न्यूनतम दर से लिया जा रहा है।
- इस कार्यशाला में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल सिंह, नीति आयोग के सचिव अभिताभ कांत, केंद्रीय उद्योग सचिव अभय गोयल सहित सभी राज्यों के परिवहन मंत्री उपस्थित थे।
- मध्य प्रदेश परिवहन एवं राजस्व मंत्री ने कार्यशाला में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रमुख नगरों में 200 से 300 किमी. के मध्य सावर्जनिक परिवहन के रूप में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी योजना बनाने जा रही है। इसके साथ ही ई-वाहन के उपयोग को सुगम बनाने के लिये यात्रा के दौरान भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर जैसे संभागीय स्थानों पर 250 ई-व्हीकल चार्ज़िंग स्टेशन बनाए जाने की योजना है।
- ई-वाहन खरीदने के लिये आम जनता को फेम 2 योजना में सब्सिडी प्रदान करना चाहिये ताकि इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलित वाहनों की तुलना में अधिक न हो और उनसे प्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाए।
- ई-वाहनों के चार्ज़िंग स्टेशन की उपलब्धता के लिये 25 प्रतिशत पेट्रोल पंपों को चिह्नित कर चार्ज़िंग स्टेशन की स्थापना अनिवार्य करना चाहिये। इसके साथ ही ई-वाहन निर्माण के क्षेत्र में रोज़गार की भी प्रबल संभावनाएँ हैं, जिससे प्रदूषण के साथ प्रदेश के युवाओं को रोज़गार भी मिल सकेगा।

75वाँ होमगार्डस् स्थापना दिवस समारोह

चर्चा में क्यों ?

- 6 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश में होमगार्डस् नागरिक सुरक्षा एवं आपदा, आपातकालीन मोचन बल का 75वाँ स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में होमगार्ड्स के जवानों ने गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को मार्च पास्ट कर सलामी दी तथा एसडीईआरएफ के जवानों ने आपदा बचाव कार्यों का अद्भुत प्रदर्शन किया।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड परेड ग्राउंड में होमगार्ड जवानों द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित फोटो-गैलरी का शुभारंभ तथा अवलोकन किया।
- कार्यक्रम में होमगार्डस् सैनिकों के 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 75 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

नोट :

- गृह मंत्री ने आपदा के समय उत्कृष्ट कार्य करते हुए लोगों की जान-माल बचाने के लिये अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कुमारी अंशिका कनौजिया को 10 हज़ार रूपए का चेक और प्रशस्ति-पत्र से पुरस्कृत किया।
- इस अवसर पर कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 में होमगार्ड द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिये 12 हज़ार 591 सैनिकों और अधिकारियों को कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित किया गया।
- गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जबलपुर में 135 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने की घोषणा की। आपदा प्रबंधन दल को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिये 45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है।
- साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि जबलपुर के मुंगेली में 165 एकड़ परिसर में 135 करोड़ रुपए की लागत से संस्थान के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही यह मूर्त रूप लेगा और जबलपुर में होमगार्डस् और एसडीईआरएफ के जवानों को बाढ़, आगजनी, भूकंप, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, रासायनिक/औद्योगिक दुर्घटनाएँ इत्यादि के समय लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण कर प्रशिक्षित किया जा सकेगा।
- गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड के अधिकारियों के कैडर संबंधी विसंगति को शीघ्र ही दूर किया जाएगा। होमगार्ड के 400 जवान आबकारी और 248 जवान खनिज विभाग में कार्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 हज़ार 425 जवानों को राज्य आपदा आपातकालीन प्रबंधन बल में (SDERF) में पदस्थ करने की कार्यवाही पर विचार-विमर्श चल रहा है।
- होमगार्ड के जवानों ने आपदा के समय अद्भुत साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है। होमगार्ड के जवानों का प्रति वर्ष कॉल ऑफ न करते हुए अब से 3 वर्ष में एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा।
- गौरतलब है कि होमगार्ड के जवान आपदा में देश की सीमाओं पर कार्य करने वाले सेना के जवानों की तरह ही कार्य करते हैं। होमगार्ड के जवानों ने इस वर्ष में 550 रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 9 हज़ार 827 लोगों की जिंदगियाँ बचाई हैं।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में होमगार्ड संगठन की स्थापना वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1947 के तहत हुई थी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) एवं टाईगर रिज़र्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास के लिये राज्य योजना में मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए अंगीकार करने की मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- वन विभाग की ग्रामों के पुनर्वास के लिये 'मुआवजा' योजना के लिये वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिये राशि 75 करोड़ की स्वीकृति की गई।
- कैंपा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4 वर्ष के लिये 285 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जाने का अनुमोदन भी किया गया।
- मंत्रि-परिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये ग्राम लोहारपुर तहसील मुरार, ज़िला ग्वालियर में स्थित कुल रकबा 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि, शून्य प्रब्याजि एवं एक रुपया वार्षिक भू-भाटक पर आवंटन करने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा 'छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा' का नाम 'राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा' किया जाने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया गया।

नोट :

- मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला, ग्वालियर का आयोजन सुचारू रूप से संचालित किया करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम में शब्द 'वाणिज्य एवं उद्योग विभाग' के स्थान पर शब्द 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग 'प्रतिस्थापित करने के लिये ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 को अनुमोदन किया।
- इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित कराने की सभी कार्यवाही करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है।

सशस्त्र झंडा दिवस

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर संचालक सैनिक कल्याण संचालनालय, ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने दिवस का प्रतीक ध्वज लगाया तथा प्रतीक-चिह्न भेंट किया गया।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सैनिक देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में कर्त्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन सैनिकों को स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश के नागरिकों द्वारा सैनिकों के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के लिये वर्ष 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इस दिवस पर मोटर वाहनों में लगने वाले कार ध्वज तथा प्रतीक ध्वज वितरित करने से संग्रहीत राशि से शहीद सैनिकों के आश्रित परिजन, दिव्यांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित आर्थिक सहायता योजनाएँ संचालित की जाती हैं।

हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता लेगा मध्य प्रदेश एच.एस.व्ही.एन

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में निगम के संचालक मंडल की 138वीं बैठक में में उत्पादित हैंडलूम उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मुहैया कराने के लिये मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली की सदस्यता लेने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये मृगनयनी एंपोरियम की भूमिका सराहनीय है। इसी क्रम में हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता ली जा रही है।
- संचालक मंडल की 137वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन, आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में नियुक्तियों पर भी निर्णय लिया गया।
- बैठक में प्रबंध संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम अनुभा श्रीवास्तव ने निगम की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी।

नोट :

प्रदेश की पहली सोलर सिटी साँची में लगेगा 6 हज़ार किलोवाट का सोलर सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति मे साँची में हुई बैठक में साँची को सोलर सिटी बनाने के लिये कार्य-योजना तैयार की गई तथा सोलर सिटी परियोजना में साँची ग्रिड सिस्टम में 6 हज़ार किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- साँची को ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम बनाने के लिये नागोरी गाँव में 20 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। सोलर सिस्टम क्षमता के फेस 1.5 मेगावाट की स्थापना के लिये अतिरिक्त 4 हेक्टयर भूमि की पहचान की जाएगी।
- गौरतलब है कि केंद्र शासन द्वारा प्रत्येक राज्य में एक शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है।
- मध्य प्रदेश शासन ने पर्यटन और राजधानी से निकटता को ध्यान में रखते हुए साँची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
- साँची के प्रत्येक घर, कृषि और उद्योग को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे बिजली का बिल, प्रदूषण, सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता में कमी आने के साथ स्थानीय अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- साँची अन्य शहरों के लिये अनुकरणीय मॉडल बनेगा। साँची की पर्यटन के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अलग पहचान होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टास्क फोर्स की बैठक

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिये गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को खेल के रूप में विकसित कर शालेय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में जन-जन तक योग के विस्तार के लिये योग आयोग का गठन किया जाएगा।
- योग की शिक्षा को शालेय स्तर पर जोड़ने से शिक्षा को रूचिकर बनाने और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संवर्धन में सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा देने की प्रभावी पद्धति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय कौशल और महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प सीखने के स्पष्ट प्रावधान हैं।
- कक्षा 6 और कक्षा 9 में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी लाने के लिये कक्षा 5वीं से 6वीं और कक्षा 8वीं से 9वीं में प्रवेश हेतु 'स्कूल चलें अभियान'चलाया जाएंगा।
- स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें राज्य पाठ्यचर्या के लिये 4 फ्रेमवर्क समूह और स्टेट केरीकुलम फ्रेमवर्क के विकास के लिये राज्य स्तर पर 25 फोकस ग्रुप गठित किये गए हैं। टास्क फोर्स में 24 अशासकीय सदस्य तथा 26 शासकीय सदस्य हैं।

नोट :

स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021

चर्चा में क्यों

- 7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा होटल ली मेरिडियन नई दिल्ली में आयोजित स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021 में मंत्रालय से वर्चुअली सहभागिता की।
- मुख्यमंत्री ने कहा है कि कि देश तभी आत्म-निर्भर बनेगा, जब राज्य आत्म-निर्भर होंगे। आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के लिये चार बिंदुओं पर आधारित रोड मैप बनाया गया है। यह 4 बिंदु हैं- भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार।
- मध्य प्रदेश सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य हैं- पहला, मध्य प्रदेश के नौजवानों में उद्यमिता के गुण का विकास करना, जिससे वे रोज़गार मांगने वाले नहीं अपितु रोज़गार देने वाले बनें और दूसरा, मध्य प्रदेश को निवेश के लिये सबसे आकर्षक राज्य बनाना।
- राज्य में निवेशकों को निवेश के लिये बेहतर वातावरण देने के उद्देश्य से अटल एक्सप्रेस-वे और प्रदेश की पूर्व से पश्चिमी सीमा तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक केंद्र तथा औद्योगिक टाउनशिप विकसित किये जाएंगे।
- प्रदेश में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है।
- स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज'की अवधारणा लागू की जा रही। इसमें 30 दिन में उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रदेश है।
- भारतमाला परियोजना के पहले चरण में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का फैसला किया गया है।
- कोविड के दौर में मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में 2019 के मुकाबले में 2021 में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉटमेंट के मामले में 33 प्रतिशत, प्रस्तावित निवेश में 67 प्रतिशत और रोजगार में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सुधारों के सफल क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश अतिरिक्त ऋण राशि का लाभ लेने वाले प्रथम 5 राज्यों में है।
- वेस्टर्न रीजन में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे राज्य को 2,373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुआ है। औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिये 'देवास निवेश क्षेत्र' तथा 'रतलाम निवेश क्षेत्र'बनाए गए हैं।
- मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है।
- प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाने के लिये 16 क्लस्टर्स चिह्नित किये गए हैं, जिनमें से केंद्र सरकार से 13 क्लस्टर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें फर्नीचर, टेक्सटाइल, पावरलूम, टॉय, गुड़, नमकीन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- लोकल को वोकल बनाने के लिये 'एक ज़िला-एक उत्पाद'योजना में प्रदेश के हर ज़िले के लिये विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है।
- निर्यातकों को मार्गदर्शन एवं प्रचार-प्रसार के लिये 'एमपी ट्रेड पोर्टल'एवं 'एक्सपोर्ट हेल्पलाइन'का शुभारंभ किया गया है।
- मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अग्रणी राज्यों में रहते हुए रेगुलेटरी कम्प्ल्यांस बर्डन (अनुपालन बोझ) को कम करने के लिये सफलतापूर्वक 1,896 सुधार लागू किये गए हैं। जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन भूमि आवंटन की प्रक्रिया लागू की गई है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 8 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिये वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन को मंज़ूरी दे दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 44 हज़ार 605 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन ज़िले लाभान्वित होंगे। साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी।
- इस परियोजना के लिये केंद्रीय समर्थन के रूप में 39 हज़ार 317 करोड़ रुपए, सहायक अनुदान के रूप में 36 हज़ार 290 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपए की धनराशि को मंज़ूर किया गया है। यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत मूर्तरूप लेने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी के स्वप्न के रूप में एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है।
- परियोजना की विस्तृत डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।
- इस परियोजना से निम्नलिखित लाभ होंगे-
  - परियोजना के मूर्तरूप लेने पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 8 लाख 11 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा तथा सूखा की समस्या खत्म होगी।
  - जल संकट से प्रभावित प्रदेश की 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।
  - परियोजना से भू-जल स्तर की स्थिति सुधरेगी।
  - परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग पूर्णरूप से मध्य प्रदेश करेगा।
  - जल आपूर्ति होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगीकरण एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तथा रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
  - स्थानीय स्तर पर आमजन में आत्मनिर्भरता आएगी तथा क्षेत्र से लोगों का पलायन रुकेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  - इस परियोजना से पन्ना ज़िले में 70 हज़ार हेक्टेयर, छतरपुर में 3 लाख 11 हज़ार 151 हेक्टेयर, दमोह में 20 हज़ार 101 हेक्टेयर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी में 50 हज़ार 112 हेक्टेयर, सागर में 90 हज़ार हेक्टेयर, रायसेन में 6 हज़ार हेक्टेयर, विदिशा में 20 हज़ार हेक्टेयर, शिवपुरी में 76 हज़ार हेक्टेयर एवं दतिया ज़िले में 14 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। साथ ही पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध होगा।

दुलार किट और कंपोस्टेबल बैग कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 8 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम भोपाल द्वारा शुरू किये गए नवाचार रिसाइकिल, रिड्यूज, रियूज के अंतर्गत बनी 'दुलार किट', कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कंपोस्टेबल कैरी बैग को सब्ज़ी मार्केट सहित अन्य बाज़ारों में उपयोग के लिये व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कैरी बैग केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, जो कुछ दिनों में आसानी से ज़मीन के अंदर ही खत्म हो जाता है।
- नगर निगम भोपाल की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर संस्था 'मन्नत'द्वारा घरों से पुराने अनुपयोगी स्वच्छ कपड़ों को एकत्रित कर इन्हें अच्छे से साफ कर और सेनिटाइज़ करने के बाद नवजात बच्चों एवं माताओं के लिये 'दुलार किट'बनाई जाती है। 'दुलार किट' ज़रूरतमंदों को नि:शुल्क वितरित की जाएगी।
- गौरतलब है कि नगर निगम भोपाल द्वारा कंपोस्टिंग के माध्यम से घर में ही कचरे का पृथक्करण करने और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने का अभियान चलाया जा रहा है।

नोट :

डाक सेवा अवार्ड-2021

चर्चा में क्यों ?

- 9 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डाक भवन के डॉ. शंकर दयाल शर्मा सभागार में मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के डाक सेवा अवार्ड-2021 समारोह में आठ विभिन्न श्रेणी में मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के कर्मचारी-अधिकारियों को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने पुरस्कार समारोह में ग्रामीण डाक सेवक अरविंद धालसे, पोस्टमैन चंद्र कीर्ति प्रसाद, पोस्टल असिस्टेंट हेलन डामोर, सुपरवाइजर ब्रजेश शर्मा, आई.पी. एवं ए.एस.पी. कॉडर नरेंद्र सविता, ग्रुप ए एवं बी कॉडर एस.के. झँवर, प्रभारी लेखा अधिकारी सी.एस. कुशवाहा को तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत किया।
- कुमारी यासमीन खान को उत्कृष्ट कार्य के लिये सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया।
- राज्यपाल ने कोविड महामारी के दौरान मध्य प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा सुकन्या समृद्धि, डाक जीवन बीमा के क्रियान्वयन, पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा वित्तीय सेवाएँ घर-घर तक पहुँचाने के प्रयासों की सराहना की।

भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू

चर्चा में क्यों ?

- 9 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश के महानगर भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून-व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और दोनों शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने पर राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों एवं सीमाओं को मेट्रो पोलिटन क्षेत्र घोषित किया है।
- गौरतलब है कि 21 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी।
- पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर नगरीय पुलिस ज़िले में 36 थानों और भोपाल नगरीय पुलिस ज़िले में 38 थानों की सीमाओं को समाविष्ट किया गया है। दोनों शहरों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे। दोनों महानगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिये अधिकारियों के पद और ज़ोन का भी निर्धारण किया गया है।
- पुलिस आयुक्त प्रणाली के लागू हो जाने से इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्त की शक्तियों एवं प्राधिकारों को मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन निहित किया गया है। पुलिस आयुक्त के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी।
- भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (1974 का 2) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में इंदौर और भोपाल नगरीय पुलिस ज़िले में पदस्थ पुलिस उपायुक्तों एवं पुलिस सहायक आयुक्तों को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- पुलिस एक्ट-1861 के अनुसार मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस का प्रशासन रहेगा। पुलिस आयुक्त पुलिस महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण एवं परिवेक्षण में रहेंगे।
- बंदी अधिनियम, 1900 के अनुसार जेल में बंद कैदियों को पेरोल और आपातकाल में पेरोल बोर्ड की अनुशंसा पर सशर्त छोड़ा जा सकेगा।
- विष अधिनियम, 1919 के तहत गैर-कानूनी ज़हर या तेजाब रखने अथवा बेचने वालों की तलाशी से बरामद जहर या तेजाब जप्त किया जा सकेगा। अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधान के अनुसार वेश्यावृत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और इस पेशे में धकेली गई महिलाओं को मुक्त करा कर उन्हें संरक्षण-गृह में भेजा जा सकेगा।

नोट :

- पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो जाने से विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1967 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
- मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रयोग करते हुए वाहनों की पार्किंग अथवा उनके रुकने के स्थान स्थानीय अधिकारियों से समन्वय कर निर्धारित किये जा सकेंगे। वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जा सकेगी। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिये या किसी सड़क या पुल की स्थिति को देखते हुए, वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित करने हेतु उपयुक्त ट्रैफिक साइन लगाये जा सकेंगे।
- इसके साथ ही मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत गुंडे-बदमाशों और ऐसे अपराधी तत्त्वों के गैंग और आदतन अपराधियों को ज़िलाबदर किया जा सकेगा। शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अंतर्गत सरकारी गोपनीय दस्तावेज़ रखने और इस अधिनियम के विरुद्ध की गई गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सकेगी।

राज्य को मिलीं 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन

चर्चा में क्यों ?

- 9 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश को कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिये 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- ये मशीन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में लगाई जाएंगी। इन मशीनों के रूप में कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा।
- अब तक राज्य के नमूने (कोविड टेस्ट) को दिल्ली भेजा जाता था, जिसकी रिपोर्ट 10 से 12 दिन बाद आती थी, लेकिन जैसे ही ये 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन राज्य में लग जाएंगी, रिपोर्ट जल्दी मिल जाएंगी।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को विशेष बजट देने के साथ ही राजधानी भोपाल में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है।

राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित

चर्चा में क्यों ?

- 10 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन के संदीपनि सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि ऊर्जा संरक्षण विषय पर राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में किया गया था।
- राज्यपाल ने प्रतियोगिता के ग्रुप-ए में प्रथम पुरस्कार डी.पी.एस. नीलबड़ भोपाल की कक्षा-6 की छात्रा वेदिका जैन को, द्वितीय पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 बी.एस.एफ. इंदौर की कक्षा-6 की छात्रा अदिति कुमारी को और तृतीय पुरस्कार आइडियल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल की कक्षा-6 के छात्र लक्ष्य शाक्य को प्रदान किया गया।
- ग्रुप-बी में प्रथम पुरस्कार बिलाबाँग हाई इंटरनेशनल स्कूल भोपाल की कक्षा-9 के छात्र भविष्य आचार्य, द्वितीय पुरस्कार एस.आई.सी.ए. स्कूल इंदौर की कक्षा-9 के छात्र राजन जांगिड़ और तृतीय पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 शिवाजी नगर भोपाल की कक्षा-9 की छात्रा प्रियांशु यादव को और दोनों श्रेणियों में 10-10 सांत्वना पुरस्कार प्रतिभागियों को प्रदान किये गए।

नोट :

- नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बच्चों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागृति और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिये कक्षा 5 से 7 तक और कक्षा 8 से 10 की दो श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- इस प्रतियोगिता में 2 हज़ार बच्चे शामिल हुए। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2021

चर्चा में क्यों ?

- 10 दिसंबर, 2021 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF) का सातवां संस्करण गोवा के पणजी में शुरू हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने शिरकत कर कई सत्रों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह संस्करण 'समृद्ध भारत के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रचनात्मकता और नवाचार का जश्न'विषय पर केंद्रित है।
- मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने 'प्रौद्योगिकी का नया युग'से संबंधित उत्सव के खंड का उद्घाटन किया। यह खंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आभासी वास्तविकता और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग जैसी सीमांत प्रौद्योगिकियों के बढ़ते क्षेत्रों पर सूचना का प्रसार करने के लिये है।
- उन्होंने 'इको फेस्टिवल'का भी उद्घाटन किया, जो उन प्रौद्योगिकियों, रणनीतियों और कार्यों से संबंधित है, जो पारिस्थितिकी रूप से स्थायी जीवन की ओर ले जाते हैं।
- ओमप्रकाश सखलेचा ने आईआईएफएस-2021 में मध्य प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भ्रमण किया। इस प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप, कार्य योजना एवं उपलब्धियों को दर्शाया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अमूल्य सहयोग प्रदान किया गया है।
- प्रदर्शनी में रिमोट सेंसिंग नवाचार विशेष है। साथ ही प्रदेश की कारीगरी और शिल्पकारी को प्रदर्शित किया गया है। इसमें बाघ प्रिंट, बांस से बने उत्पाद, अगरिया कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे के उत्पाद और कलाकृति जैसी कई वस्तुएँ शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि आईआईटीएफ-2021 का उद्देश्य भारतीय पारंपरिक कला और शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना है। मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने गोवा के पारंपरिक शिल्पकार, पँश्री विनायक खेडेकर के साथ आईआईएसएफ के तहत 'पारंपरिक शिल्प और कारीगर महोत्सव'का उद्घाटन भी किया।

'ड्रोन मेला'

चर्चा में क्यों ?

- 11 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (एमआईटीएस) में केंद्रीय नागरिक उडन्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लगभग 20 कंपनियों ने अपने ड्रोन का प्रदर्शन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 'ड्रोन मेला'में मौजूद युवाओं और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाएंगे। ड्रोन एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है, जिसका उपयोग जन-कल्याण एवं सुशासन में किया जा सकता है।
- ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में किया जा सकता है। इससे किसान हानिकारक रसायनों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। यह तकनीक कम खर्चीली है। ड्रोन तकनीक से 25 प्रतिशत तक खाद की बचत होती है।

नोट :

- केंद्रीय नागरिक उडन्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भविष्य में ड्रोन तकनीक से विश्व की अर्थव्यवस्था और जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश देश का अव्वल राज्य है। रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में ड्रोन तकनीक क्रांतिकारी साबित हो रही है। यह तकनीक गरीबी को समृद्धि में तब्दील करने का साधन बनी है। ड्रोन तकनीक से 3 लाख युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में पाँच ड्रोन स्कूल-ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में खोले जाने की घोषणा की। इन स्कूलों के ज़रिये ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोज़गार मिले, साथ ही ड्रोन तकनीक का भी विकास और आत्मनिर्भरता में भरपूर इस्तेमाल हो।
- इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर के एमआईटीएस में ड्रोन एक्सीलेंसी सेंटर खोलने की घोषणा भी की। इसके लिये एक कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया गया है। ड्रोन मेले में अन्य कंपनियों ने भी एमओयू किये हैं।
- ड्रोन मेला में भाग लेने आईं लगभग एक दर्जन कंपनियों ने अपनी-अपनी सेवाओं का प्रदर्शन किया। ड्रोन मेले में थ्रॉटल एयरोस्पेस सिस्टम बैगलूरू, एस्टेरिया एयरोस्पेस लिमिटेड बैगलूरू, मारूत ड्रोंस हैदराबाद, ड्रोन डेस्टिनेशन नई दिल्ली, एग्री उड़ान प्रा.लि. अहमदाबाद, ग्वालियर पुलिस, बीसा सिम्यट नई दिल्ली सहित अन्य कंपनियों ने उर्वरक बीज छिड़काव व परिवहन, सर्विलांस, वनीकरण, ज़रूरी वस्तुओं का परिवहन इत्यादि का अपने-अपने ड्रोन से प्रदर्शन किया।

ई-व्हीकल्स रोड-शो

चर्चा में क्यों ?

- 11 दिसंबर, 2021 को भोपाल नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसंबर) के उपलक्ष्य में इलेक्ट्रिक वाहन की उपयोगिता के प्रति जन-जागृति तथा आमजन में इसके प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि से भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड-शो का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस रोड शो का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ किये गए ऊर्जा साक्षरता अभियान में प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा-संरक्षण प्रबंधन एवं इसके सदुपयोग के बारे में जागरूक करना तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और पेट्रोल एवं डीज़ल पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने के लिये ई-व्हीकल को प्रोत्साहित करना है।
- इस रोड-शो में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा, ई-स्कूटर एवं ई-चार पहिया वाहन आदि शामिल थे। रोड-शो में शामिल ई-वाहन ऊर्जा विकास निगम परिसर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों-तितली चौक, लिंक रोड क्रमांक-1, न्यू मार्केट, मिंटो हॉल, पुलिस कंट्रोल रूम, शहीद स्मारक से 6 नंबर होते हुए वापस ऊर्जा भवन पहुँचे।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा ई-मोबिलिटी मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिये 'गो-इलेक्ट्रिक कैम्पेन' प्रारंभ किया है।
- भोपाल नगर निगम के मुख्य अभियंता भुवनेश कुमार पटेल ने बताया कि परिवहन क्षेत्र में कुल ऊर्जा का 18 प्रतिशत व्यय होता है, जिसमें लगभग 94 मिलियन टन ऑयल की खपत होती है। 'इलेक्ट्रिक व्हीकल'को प्रमोट करने से ऑयल की बचत के साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिये विशेष फेम (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल) भी लॉन्च किया है।

मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महँगाई राहत की दर में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

- 14 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों की महँगाई राहत की दर में वृद्धि का आदेश जारी किया। यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2021 से लागू मानी जायेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने राज्य शासन के पेंशनरों की महँगाई राहत 10 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। जिन्हें छठा वेतनमान के तहत पेंशन मिल रही थी, उनकी महँगाई राहत 10 प्रतिशत बढ़कर 164 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान के तहत मिल रही थी, उनकी महँगाई राहत 5 प्रतिशत बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी।
- यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी, परंतु यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी।
- 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत देय होगी।
- उपरोक्त महँगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी।
- सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किये गए अनुकंपा भत्ता पर भी इस महँगाई राहत की पात्रता होगी।
- ऐसे पेंशनर्स, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।
- यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों/निगमों आदि में सिविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के अंतर्गत पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

EDII को उद्यमिता में 'उत्कृष्टता केंद्र' का दर्जा मिला

चर्चा में क्यों ?

- 14 दिसंबर, 2021 को भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), अहमदाबाद के महानिदेशक सुनील शुक्ला ने बताया कि हाल ही में EDII को भारत सरकार के उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा उद्यमिता में 'उत्कृष्टता केंद्र' का दर्जा प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, 1983 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और संस्थान निर्माण के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।
- यह समावेशी विकास के लिये और मध्य भारत में उद्यमिता हेतु एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये भोपाल में अपने केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से काम करता है।
- यह उद्यमिता शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा संस्थानों, सरकार और उद्योग के बीच परस्पर निर्भरता एवं सहयोग का माहौल बनाने हेतु सामूहिक प्रयास करता है। साथ ही यह मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, छात्रों, कारीगरों, कृषकों आदि के उत्थान के उद्देश्य से एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है।
- EDII मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्यों के लिये लगा हुआ है, जिसमें चंदेरी और महेश्वर में हथकरघा, बैतूल में टेराकोटा और ग्वालियर में कालीन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- EDII डीएसटी, भारत सरकार के समर्थन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि के उद्यमियों को विकसित करने तथा संकाय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन के पूल को विकसित करने में लगा हुआ है।
- डॉ. सुनील शुक्ला ने कहा कि EDII ने मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थानों, जैसे- मध्य प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर और सरकारी संस्थानों के साथ कई अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- राज्य में प्रमुख शिक्षा संस्थानों के सहयोग से EDII का लक्ष्य फिनटेक, एडुटेक, क्लेनटेक, हेल्थटेक, बायोटेक आदि जैसे प्रौद्योगिकी गहन डोमेन में छात्र उद्यमिता के लिये एक अनुकूल माहौल बनाना है।

नोट :

जबलपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिये 21 एकड़ भूमि आवंटित

चर्चा में क्यों ?

- 15 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने जबलपुर के औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में टेक्नोलॉजी सेंटर के लिये 21 एकड़ से अधिक भूमि के आवंटन की प्रशासकीय स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- जबलपुर में उद्योगों की नई तकनीक से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिये टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने भी इस प्रोजेक्ट के लिये 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
- इस आवंटित पट्टे की अधिकतम अवधि 99 वर्षों की होगी। इसके बाद ज़मीन पर पुन: गतिविधि संचालित होने की दशा में लीज का नि:शुल्क नवीनीकरण किया जाएगा।
- इस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना से जबलपुर एवं आसपास के ज़िलों की औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिलेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा डिज़ाइन, टेस्टिंग, टूलिंग, इनक्यूबेशन, ट्रेनिंग इत्यादि के रूप में उद्योगों को प्रत्यक्ष तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- जबलपुर, महाकौशल क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। यहाँ स्थापित उद्योगों को नई तकनीक की जानकारी के साथ उत्पादों के प्रोटोटाइप तैयार कराने में मदद मिलेगी। इंजीनियरिंग और आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को वास्तविक मशीनों पर काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही आयुध निर्माणियों को भी फायदा होगा।

टीकाकरण महाभियान-10

चर्चा में क्यों ?

- 16 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाभियान-10 चलाया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये एक दिन में 15 लाख वैक्सीन की डोज लगाकर एक बार फिर से प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है।

प्रमुख बिंदु

- टीकाकरण महाभियान-10 में रात्रि 9 बजे तक 14 लाख 89 हज़ार 331 नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश को मिली इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल ने अहम रोल अदा किया है।
- मध्य प्रदेश में इस टीकाकरण महाभियान में 11 हज़ार से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की सभी व्यवस्थाएँ की गई थीं। केंद्रों पर सुबह 9 बजे से टीका लगना प्रारंभ हुआ, जो दिन भर चलता रहा।
- अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 18 लाख 5 हज़ार 926 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 4 करोड़ 52 लाख 42 हज़ार 372 नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं।
- मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जल्द-से-जल्द मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 21 जून, 2021 से टीकाकरण महाभियान की श्रृंखला चलाई जा रही है।
- टीकाकरण महाभियान को सफल बनाने के लिये जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों, जन-अभियान परिषद के कार्यकर्त्ताओं सहित स्वास्थ्य विभाग के लोग कार्य कर रहे हैं।

नोट :

मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस समारोह

चर्चा में क्यों ?

- 17 दिसंबर, 2021 को भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड के निरीक्षण एवं मार्च पास्ट के बाद उत्कृष्ट सेवा के लिये पुलिस अधिकारियों को पदक प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा, ड्रग माफिया का पूरी तरह सफाया और साइबर क्राइम पर प्रभावी कार्यवाही मध्य प्रदेश पुलिस के सामने प्रमुख चुनौतियाँ हैं। मध्य प्रदेश पुलिस को जो भी दायित्व सौंपा गया है, वह पूरी दक्षता, दृढ़ता, कर्त्तव्यनिष्ठा और ज़िम्मेदारी से निभाया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ने अदम्य साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्थापना वर्ष 1956 से लेकर 2020 तक 877 पुलिस कर्मियों ने शहादत दी है। इन पुलिसकर्मियों ने प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने की महान परंपरा स्थापित की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1956 से लेकर 26 जनवरी, 2021 तक 429 वीरता, 229 विशिष्ट सेवा और 1508 मेधावी पदक पुलिस के सदस्यों ने प्राप्त किये हैं।
- मुख्यमंत्री ने वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक अरविंद सक्सेना (अपर परिवहन आयुक्त), धर्मवीर सिंह (पुलिस अधीक्षक, सतना) को प्रदान किया।
- विशिष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक अनुराधा शंकर (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण), प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध), संतोष कुमार उपाध्याय (उप पुलिस अधीक्षक यातायात, इंदौर), भरत कुमार भावसार (सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक), राकेश मोहन दीक्षित (सेवानिवृत्त निरीक्षक), डॉ. फरीद बजमी (ग्रंथालय अधिकारी), नरेन्द्र कुमार गंगराड़े (निरीक्षक) और अजय तुरकई (निरीक्षक) को प्रदान किये।
- मुख्यमंत्री ने सराहनीय सेवा के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक आर.आर.एस. परिहार (पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर), मोनिका शुक्ला (पुलिस अधीक्षक, विदिशा) तथा मनोज कुमार सिंह (सहायक पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल) सहित 32 पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों को प्रदान किये।
- मुख्यमंत्री ने जगदीश सिंह सिद्धू (निरीक्षक थाना कोतवाली रायसेन), गौरी शंकर व्यास (प्रधान आरक्षक (चालक), थाना खुरई सागर), राजेश कुमार राजपूत (आरक्षक थाना बरेली, रायसेन), पुष्पेंद्र सिंह रावत (आरक्षक डीआपी लाईन, रायसेन) को जीवन रक्षा पुलिस पदक प्रदान किये।
- मुख्यमंत्री ने सम्मान स्वरूप 32 बोर पिस्टल पुरस्कार स्व. संजीव कुमार सिंह (भारतीय पुलिस सेवा सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक) की धर्मपत्नी ज्योति सिंह को प्रदान किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश पुलिस गान का लोकार्पण भी किया।

'वास्तुकला रचना प्रतियोगिता' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 17 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने मैनिट के सिविल विभाग के सभागार में 'भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान' विषय पर राष्ट्रीय स्तर की वास्तुकला रचना प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही इस वास्तुकला रचना प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वैज्ञानिकों के अतुलनीय योगदान को एक स्मारक और संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत कर न सिर्फ सम्मान और पहचान देना है, बल्कि भारतीयों की वर्तमान पीढ़ियों के समक्ष उस योगदान को एक अत्यंत रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत भी करना है।
- यह प्रतियोगिता वर्तमान में अध्ययनरत् स्कूली छात्रों के साथ-ही-साथ अध्ययनरत् और कार्यरत् वास्तुविदों एवं योजनाकारों को एक अनूठा मौका देगी, जिससे वे इन महान विभूतियों और उनके अतुल्य योगदानों को अपनी रचनात्मकता से एक बड़े स्तर पर प्रस्तुत कर जनसाधारण के बीच उनके जीवन और योगदान का संदेश प्रेषित कर प्रेरणा का संचार कर पाएंगे।
- इस प्रतियोगिता के अंतर्गत स्मारक और संग्रहालय के आकल्पन को उज्जैन के तारामंडल परिसर स्थित 6 एकड़ के स्थान के लिये प्रस्तावित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने जा रही इस प्रतियोगिता को मैनिट, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान भारती, आई.पी.एस. एकेडमी इंदौर एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मिल कर आयोजित कर रही हैं।

'इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कांक्लेव-2021' अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

- 18 दिसंबर, 2021 को इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ राहुल नरोंहा ने इंडिया टुडे समूह की ओर से 'इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कान्क्लेव 2021 में' मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 'मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर' का पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इंडिया टुडे द्वारा प्रति वर्ष राज्यों को कृषि क्षेत्र में दो कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाता है। यह श्रेणियाँ ओवर ऑल बेस्ट तथा मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट इन एग्रीकल्चर हैं। मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार कृषि से आय में वृद्धि के लिये नवीनतम तकनीकों को अपनाने और मंडी सुविधा को कृषकों के लिये सुलभ, सरल बनाने की दिशा में किये गए प्रयासों के लिये प्रदान किया गया है।
- मध्य प्रदेश को मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर में लगातार चौथी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन का उपार्जन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही किसानों की कृषि से आय में वृद्धि की दिशा में कार्य करते हुए वैल्यू एडीशन पर विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
- सात प्रमुख फसलों के संबंध में वैल्यू एडीशन के लिये आवश्यक सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की सेवाएँ ली गई हैं। उपार्जन प्रक्रिया को भी ऐप के माध्यम से प्रदेश में सरल बनाया गया है। प्रदेश में कृषकों को कृषि के लिये आधुनिकतम उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित

चर्चा में क्यों ?

- 18 दिसंबर, 2021को मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं ज़िला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिये आरक्षित पदों के लिये जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये ज़िला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हज़ार 353 पद आरक्षित हैं।

चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव-2022 मोबाइल एप

चर्चा में क्यों ?

- 19 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित 'चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव-2022 (सीबीएफएफ-2022)' के एप का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री सारंग ने कहा कि सिनेमा, समाज को सिर्फ उसकी स्थिति ही नहीं बताता है बल्कि समाज को कैसा होना चाहिये, यह भी बताता है। समाज को दिशा देना ही सिनेमा की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि फिल्मों से जुड़े व्यक्ति को यह विचार करना चाहिये कि उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जो युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर लेकर जाए, क्योंकि युवा फिल्म कलाकारों से प्रेरणा लेते हैं।
- चित्र भारती का यह एप नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। एप एंड्राइड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन पर उपयोग किया जा सकेगा। इस एप पर फिल्म फेस्टिवल की संपूर्ण जानकारी रहेगी।
- इस एप से प्रतिभागी मास्टर क्लास, फिल्मों की स्क्रीनिंग, कार्यक्रम स्थलों, आने वाली फिल्म, अभिनेताओं, कलाकारों और विषय-विशेषज्ञों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एप पर पंजीयन कर फिल्म फेस्टिवल के वॉलेंटियर बन सकते हैं। प्रतिभागी विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और फेस्टिवल के संबंध में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं।
- भारतीय चित्र साधना के महासचिव अतुल गंगवार ने बताया कि 18 से 20 फरवरी, 2022 को भोपाल में होने जा रहे इस लघु फिल्म उत्सव के लिये देशभर से 600 से अधिक शार्ट फिल्में प्राप्त हो चुकी हैं। चित्र भारती के माध्यम से फिल्म के क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ युवाओं को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस फिल्मोत्सव में देश के बड़े फिल्म कलाकारों एवं फिल्म निर्माताओं से मिलने का अवसर मिलेगा।

विक्रमोत्सव-2021

चर्चा में क्यों ?

- 20 दिसंबर, 2021 को महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा भारत उत्कर्ष और नव-जागरण पर एकाग्र तीनदिवसीय 'विक्रमोत्सव-2021' का उद्घाटन जनजातीय संग्रहालय में महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य'की प्रस्तुति के साथ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विक्रमोत्सव के शुभारंभ अवसर पर महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित आयोजन प्राय: उज्जैन तक ही सीमित रहते आए हैं, जबकि विक्रम कीर्ति सार्वभौमिक रही है। इसी दृष्टि से विक्रमोत्सव श्रृंखला को उज्जैन के परकोटे से बाहर निकाल कर पहली बार भोपाल लाया जा रहा है।
- यह समारोह श्रृंखला भोपाल के अलावा पुणे, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि सांस्कृतिक केंद्रों पर भी आयोजित होगी।

नोट :

- तिवारी ने बताया कि उज्जैन में पिछले दिनों भारत-विक्रम शीर्षक से व्याख्यान श्रृंखला का आरंभ किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। भारत उत्कर्ष एवं नव-जागरण पर केंद्रित यह व्याख्यान माला देश के प्रमुख शहरों में भी आयोजित किये जाने की योजना है।
- विक्रमोत्सव के पहले दिन संजय मालवीय के निर्देशन में विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति, उज्जैन ने महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' की प्रस्तुति दी। लगातार तीन दिन चलने वाले विक्रमोत्सव में दो अन्य नाटकों की प्रस्तुति होगी।

देव श्रीमाली की पुस्तक 'बिछड़े कई बारी बारी' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 20 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली की किताब 'बिछड़े कई बारी बारी' का विमोचन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह पुस्तक उन पत्रकारों के योगदान पर आधारित है, जिन्होंने कोरोना काल में अपने कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान जान गँवाई है।
- इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि यह पुस्तक अपनेआप में एक तरह का वृत्तांत है। कोरोना योद्धाओं की स्मृति को सदा बनाए रखने के लिये देव श्रीमाली ने यह पुस्तक लिखी है।
- विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में कई वर्गों ने सरकार के साथ मिलकर काम करने में अहम भूमिका निभाई है, इनमें पत्रकार भी प्रमुख रूप से शामिल हैं।
- आम जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करने में जहाँ मीडिया की अहम भूमिका रही, वहीं दूसरी ओर सरकार को समय-समय पर चेतावनी भी दी गई। आज मध्य प्रदेश कोविड-19 टीकाकरण में काफी बेहतर स्थिति में है और इसे जन- अभियान बनाने में मीडिया ने भी अपनी भूमिका निभाई है।

'निर्झरणी महोत्सव'

चर्चा में क्यों ?

- 20 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा ज़िला प्रशासन- अलीराजपुर के सहयोग से तीनदिवसीय 'निर्झरणी महोत्सव' का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- देश की 75वीं स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को समर्पित और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति और नदियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिये 20 से 22 दिसंबर तक रजवाड़ा परिसर में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
- 20 दिसंबर को सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र समिति, रीवा द्वारा आदिवासी भगोरिया नृत्य, कोरकू आदिवासी गडली-थप्ती नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, गोंड आदिवासी धानदार नृत्य, गुजरात का राठवा आदिवासी नृत्य के साथ-साथ महानायक चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नाटक 'गगन दमामा बाज्यो' पर केंद्रित प्रस्तुति दी गई।
- दूसरे दिन 21 दिसंबर को भील आदिवासी नृत्य, निमाड़ लोकनृत्य एवं वन निवासी लीला नाट्य भक्तिमति शबरी की प्रस्तुति होगी।
- तीसरे दिन 22 दिसंबर को भील आदिवासी नृत्य, भारिया आदिवासी भादम नृत्य और वनवासी लीला नाट्य निषादराज गुह्या का प्रदर्शन किया जाएगा।

नोट :

खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग के पहले चरण का समापन

चर्चा में क्यों ?

- 15 से 21 दिसंबर, 2021 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेले गए खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग (अंडर-21) का पहला चरण समाप्त हो गया। इसमें मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने 6 मैच खेले।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि महिला हॉकी लीग तीन चरणों में खेली जा रही है, जिसका पहला चरण 21 दिसंबर को समाप्त हुआ।
- पहले चरण का अंतिम मैच मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी और हरियाणा हॉकी अकादमी के बीच 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने अब तक खेले गए छह मैचों में 22 गोल किये हैं। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के तीन मैच ड्रॉ रहे और अकादमी ने तीन मैच जीते।
- मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ग्रुप-बी में 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, वहीं हरियाणा हॉकी अकादमी 16 अंकों के साथ पहले स्थान पर है।
- गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG), पूर्व में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स (KISG), भारत में जनवरी या फरवरी में दो श्रेणियों, अर्थात् अंडर-17 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर-21 वर्ष के कॉलेज के छात्र के लिये आयोजित होने वाले वार्षिक राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं।

राज्यपाल ने अरबिंदो विश्वविद्यालय में केंद्रीय नैदानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

- 20 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय, इंदौर में सिकल सेल एनीमिया परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही सिकल सेल क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सिम्युलेटर लैब और केंद्रीय नैदानिक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि यह अभियान मध्य प्रदेश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त बनाने में एक नई दिशा देगा।
- श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय के संस्थापक विनोद भंडारी ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया परियोजना के माध्यम से प्रदेश के एनीमिया रोग से पीड़ित आदिवासी बेल्ट के लोगों को निःशुल्क इलाज कराने का प्रयास किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, प्रशासन और समाज की भागीदारी से सिकल सेल एनीमिया मुक्त राज्य बनाने की अवधारणा को सार्थक रूप दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने किया '1857 की क्रांति और नीमच' पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 23 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में डॉ. सुरेंद्र शक्तावत द्वारा लिखित पुस्तक 'अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति और नीमच' पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- पुस्तक के लेखक डॉ. सुरेंद्र शक्तावत इतिहास संकलन समिति नीमच के संयोजक तथा नीमच ज़िला पुरातत्त्व संघ के सदस्य हैं। शक्तावत बालकवि बैरागी महाविद्यालय कनावटी के प्राचार्य हैं।
- डॉ. शक्तावत ने ग्राम गाथा पिपलिया रावजी, इतिहास की नजर में नीमच ज़िले के स्वतंत्रता सेनानी, मालवा का लोकनाट्य मंच और अन्य विधाएँ, मालवा की चित्रकला आदि पुस्तकें लिखी हैं।

नोट :

- प्रस्तुत ग्रंथ में अंग्रेज़ों की क्रूरता का प्रतीक भूमिया खेड़ी का अग्निकांड, निंबाहेड़ा के निर्दोष पटेल ताराचंद की हत्या और तात्या की फाँसी पर अंग्रेज़ी न्याय की स्व-प्रमाणित पोल खोलने का प्रयत्न कर लेखक ने सिद्ध किया है कि नीमच की क्रांति केवल सैन्य विद्रोह न होकर जनक्रांति थी, जिसमें स्थानीय जन-समुदाय की भी भागीदारी रही।
- मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे के अनुसार डॉ. सुरेंद्र शक्तावत द्वारा लिखित पुस्तक क्षेत्रीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नीमच के क्रांतिकारियों की विशिष्ट भूमिका रही।
- मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम क्रांति का सूत्रपात नीमच की लाल माटी से 3 जून, 1857 को मोहम्मद अली बेग ने किया था। क्रांतिवीर अलीबेग नीमच से विजय पताका लेकर चित्तौड़, बनेड़ा, नसीराबाद, देवली होते हुए आगरा पहुँचे, जहाँ अंग्रेज़ों पर विजय प्राप्त की।

'तानसेन समारोह'

चर्चा में क्यों ?

- 26 दिसंबर, 2021 को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव विश्व संगीत समागम 'तानसेन समारोह'का संगीतधानी ग्वालियर में भव्य एवं रंगारंग शुभारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- ग्वालियर के हजीरा स्थित संगीत सम्राट तानसेन की समाधि के समीप सिद्धेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर की थीम पर बने भव्य एवं आकर्षक मंच पर अतिथियों ने कन्या पूजन कर तानसेन समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया।
- समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में देश के सुप्रतिष्ठित सितार वादक पं. कार्तिक कुमार (मुंबई) और सुविख्यात घट्म वादक पँभूषण पं. विक्कू विनायकरम (चेन्नई) को क्रमशः वर्ष 2013 और 2014 के 'राष्ट्रीय कालिदास सम्मान'से अलंकृत किया गया।
- दोनों मूर्धन्य संगीत साधकों को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त सम्मान राशि, प्रशस्ति पटिका एवं शॉल-श्रीफल भेंट किये गए।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तानसेन अलंकरण एवं कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि को बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए करने तथा तानसेन समारोह की तर्ज़ पर संगीत सम्राट तानसेन के समकालीन महान संगीत मनीषी बैजू बावरा की स्मृति में 'बैजू बावरा समारोह'का आयोजन भी शुरू करने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि महान संगीत मनीषी तानसेन की याद में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह का शताब्दीवाँ समारोह वर्ष 2024 में धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उडन्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य अतिथियों ने पं. रविशंकर पर केंद्रित एक पुस्तक का विमोचन भी पर किया।
- गौरतलब है कि सिंधिया राज्यकाल में ही सन् 1924 में तानसेन समारोह का शुभारंभ हुआ था। यह 97वाँ तानसेन समारोह है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 भोपाल में होंगे

चर्चा में क्यों ?

- 26 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी भोपाल शहर में किये जाने तथा खेलो इंडिया योजना के प्रथम चरण में ग्राम नाथू बरखेड़ा में 20.42 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि ग्राम नाथू बरखेड़ा भोपाल में निर्मित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं उपकरण पर लगभग 176.59 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

नोट :

- यह कार्य तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन शामिल हैं।
- द्वितीय चरण में ग्राम नाथू बरखेड़ा भोपाल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा तृतीय चरण में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 10 हज़ार लोगों की क्षमता वाले फुटबॉल स्टेडियम, 4 हज़ार क्षमता के दो हॉकी स्टेडियम, पार्किंग, इंटर्नल एवं सर्विस मार्ग, लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर, सोलर पैनल, बाउंड्री वाल, गेट, गॉर्डरूम, सीवेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट आदि से लैस होगा।

जैव-विविधता संरक्षण के लिये 9 ज़िलों में विकसित होंगे आयुष वन

चर्चा में क्यों ?

- 26 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिर-स्थाई बनाने के लिये प्रदेश के 9 ज़िलों में आयुष वन विकसित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- वन मंत्री ने बताया कि अगले साल पन्ना, भोपाल, गुना, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर, शहडोल और अनूपपुर ज़िले में 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन विकसित किये जाएंगे। इसी तरह वर्ष 2023-24 में स्थानीय प्रजातियों और जड़ी-बूटी वाले पौधों का रोपण कराया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि नर्मदा उद्गम स्थल के पास 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन की स्थापना की जा चुकी है। इस व्यवस्था से औषधीय पौधे लगने से पर्यटकों के लिये प्रकृति दर्शन का आकर्षण केंद्र बनेगा।
- वन मंत्री ने बताया कि जैव-विविधता संरक्षण के लिये विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने की दिशा में जैव-विविधता को बचाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने विश्वास दिलाया। कि आयुष वन जैसे स्थल पर्यावरण ज्ञान केंद्र के रूप में उपयोगी होंगे।

सुशासन सूचकांक, 2021 में मध्य प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

- 25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप 'बी' में मध्य प्रदेश को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- जीजीआई-2021 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों- समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में बाँटकर रैंकिंग दी गई है। जीजीआई-2021 तैयार करने के लिये 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है।
- मध्य प्रदेश ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.887 स्कोर के साथ ग्रुप 'बी' में प्रथम रैंक प्राप्त किया है, वहीं गुजरात ने ग्रुप 'ए' में प्रथम रैंक प्राप्त की है।
- मध्य प्रदेश ने पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में अपने स्कोर में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.85 था, जो अब बढ़कर 4.89 हो गया है।
- मध्य प्रदेश ने मूलत: सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र तथा समाज कल्याण एवं विकास क्षेत्र में सुधार किया है।
- सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग तथा स्कोर निम्नलिखित हैं-

क्षेत्र	मध्यप्रदेश की रैंकिंग	स्कोर
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	प्रथम	0.652
2. वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र	चतुर्थ	0.646
3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र	8वीं	0.380

नोट :

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	7वीं	0.185
5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र		द्वितीय 0.662
6. आर्थिक शासन क्षेत्र	द्वितीय	0.477
7. समाज कल्याण एवं विकास	द्वितीय	0.666
8. न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा	5वीं	0.282
9. पर्यावरण क्षेत्र	6वीं	0.308
10. नागरिक केंद्रित शासन	5वीं	0.627

पँश्री डॉ. कपिल तिवारी ने किया हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 27 दिसंबर, 2021 को भोपाल हाट में पँश्री डॉ. कपिल तिवारी, अपर मुख्य सचिव जे.एन. कंसोटिया और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह हैंडलूम एक्सपो 9 जनवरी, 2022 तक चलेगा, जो सैलानियों के लिये दोपहर 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहेगा।
- यहाँ विभिन्न 15 राज्यों की सांस्कृतिक छटा देखने को मिलेगी। इसमें मध्य प्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक एवं दक्षिण भारत के बुनकर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं।
- विभिन्न स्टॉल पर देश के राज्यों के उत्पाद मौजूद है। हैंडलूम एक्सपो संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, भोपाल तथा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में हो रहा है। इसमें नियमित सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी। एक्स पो के पहले दिन दक्षिण शैली के नृत्य की प्रस्तुति हुई।

नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

- 27 दिसंबर, 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिये अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है, वहीं केरल शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट को तीन भागों में बाँटा गया था- बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिज़ोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा जबकि नागालैंड सबसे नीचे रहा।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दादरा और नगर हवेली दूसरे नंबर पर तथा दिल्ली तीसरे नंबर पर है।
- बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में मध्य प्रदेश 36.72 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 17वें स्थान पर है। वहीं केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले, तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दुसरे एवं तेलंगाना 69.96 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
- नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक हैं।

नोट :

उज्जैन में खुलेगा आईआईटी इंदौर का सेटेलाइट कैंपस

चर्चा में क्यों ?

- 28 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्राचीन वैभवशाली ज्ञान परंपरा के अनुरूप उज्जैन को प्रौद्योगिकी और ज्ञान-विज्ञान के एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर का सेटेलाइट कैंपस खोला जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 100 एकड़ भूमि पर स्थापित यह कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। अपनी तरह का यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। रोजगार और स्व-रोजगार के प्रोत्साहन में भी यह कैंपस महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
- उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह कैंपस हर दृष्टि प्रशासनिक, अकादमिक निर्णय के लिये स्वतंत्र होगा। कैंपस में छात्रावास और शिक्षकों के लिये आवास भी होंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध सुविधाएँ एवं पाठ्यक्रम संचालित किये जाएंगे। प्रारंभिक चरण में चार राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण केंद्र और इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क खोले जाने का प्रस्ताव भी है।
- डॉ. यादव ने बताया कि यह रिसर्च पार्क इंदौर-उज्जैन और आस-पास के सभी क्षेत्रों की औद्योगिक इकाई को शोध कार्य में मदद करेगा। साथ ही स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करेगा। इसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 100-150 अधिक कंपनियों को जोड़ा जाएगा। अभी आईआईटी चेन्नई और मुंबई में ऐसे ही रिसर्च पार्क कार्य कर रहे हैं।
- मालवा क्षेत्र में रोज़गार और स्व-रोज़गार निर्माण की दिशा में इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क की अहम भूमिका होगी। स्पोर्ट्स साइंस में स्पोर्ट्स में उपयोग की जाने वाली डिवाइसेज़ और इक्विपमेंट पर भी यहाँ रिसर्च करना प्रस्तावित है।
- उन्होंने बताया कि जल संसाधन प्रबंधन के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण केंद्र होगा। जहाँ जल के संबंध में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जल संसाधन पर शोध कार्य किया जाएगा। वॉटर मैनेजमेंट पर आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाएंगे। मध्य प्रदेश में वॉटर कंजर्वेशन तकनीक को बढ़ाने और जल से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करने में केंद्र यह मदद करेगा।
- मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विश्व की श्रेष्ठतम भारतीय काल गणना और कैलेंडर सिस्टम का केंद्र स्थान उज्जैन रहा है। काल गणना और खगोलीय विज्ञान में उज्जैन के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए यह सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग और एस्ट्रो फिजिक्स के पाठ्यक्रम के साथ रिसर्च और प्रयोगशाला भी स्थापित होगी।
- भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश का मॉडल बनेगा, जिसमें कृषि, ज्ञान परंपरा, हॉलिस्टिक मेडिसिन, प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने जैसे विषयों पर शोध होंगे।
- सेंटर में डिजिटल ह्युमेनीटीज, एनवायर्नमेंटल ह्युमेनीटीज, डेवलपमेंट स्टडीज पर नेशनल रिसर्च सेंटर और सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिये ह्युमेनीटीज और सोशल साइंस एजुकेशन पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा।

विभिन्न निगम, मंडल, बोर्ड तथा प्राधिकरण के अध्यक्षों को तथा कैबिनेट मंत्री का दर्जा और उपाध्यक्षों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

- 29 दिसंबर, 2021 को राज्य शासन ने निगम, मंडल, बोर्ड और प्राधिकरण के नव-नियुक्त अध्यक्षों को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये हैं। केबिनेट मंत्री का दर्जा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्राप्त होगा।

प्रमुख बिंदु

- इसी प्रकार निगम, मंडल, बोर्ड और प्राधिकरण के नव-नियुक्त उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करने के आदेश भी जारी हो गए हैं। यह भी संबंधित नव-नियुक्त उपाध्यक्षों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्राप्त होगा।

नोट :

- मध्य प्रदेश शासन ने शैलेंद्र बरूआ को मध्य प्रदेश पाठ्य-पुस्तक निगम, शैलेंद्र शर्मा को मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड, जितेंद्र लिटौरिया को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, इमरती देवी को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एंदल सिंह कंषाना को मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गिर्राज दंडोतिया को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, रणवीर जाटव को संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जसवंत जाटव को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम तथा मुन्नालाल गोयल को मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है।
- इसी प्रकार रघुराज कंसाना को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, आशुतोष तिवारी को मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, विनोद गोंटिया को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित, जयपाल चावड़ा को इंदौर विकास प्राधिकरण, अमिता चपरा को मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, निर्मला बारेला को मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम और सावन सोनकर को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित का अध्यक्ष बनाया गया है।
- वहीं राज्य शासन ने प्रहलाद भारती को मध्य प्रदेश पाठ्य-पुस्तक निगम, नरेंद्र बिरथरे को मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड, राजकुमार कुशवाहा को मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अजय यादव को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, मंजू दादू को मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित, राजेंद्र सिंह मोकलपुर को दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रमेश खटीक को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित एवं राजेश अग्रवाल को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का उपाध्यक्ष बनाया है।

उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को मिला नैक से सर्वोच्च ए+ ग्रेड

चर्चा में क्यों ?

- 29 दिसंबर, 2021 को उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल (नैक) में सर्वोच्च ग्रेड ए+ मिला है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महाविद्यालय ने प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में से सबसे ज़्यादा अंक अर्जित किये हैं। यह गौरव की बात है। महाविद्यालय ने 3.48 अंक के साथ ए+ ग्रेड अर्जित किया है।
- उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में 55, द्वितीय चरण में 75 तथा तृतीय चरण में 80 शासकीय महाविद्यालय को नैक ग्रेड दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। लगभग 85 प्रतिशत पात्र शासकीय महाविद्यालय को वर्ष 2023 तक नैक ग्रेड मिल सकेगी।
- उच्च शिक्षा में सुधारों की इसी श्रृंखला में सभी महाविद्यालयों में मास्टर फैसिलिटेटर नियुक्त किये गए हैं। शासन द्वारा सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के लिये भी मदद की जा रही है।
- गौरतलब है कि नैक मूल्यांकन एसएसआर पर ही निर्धारित होता है। प्रदेश के लगभग 107 शासकीय महाविद्यालयों को अभी तक नैक ग्रेड प्राप्त हैं।

पंचायतों का फिर से होगा परिसीमन

चर्चा में क्यों ?

- 30 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अध्यादेश के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में एक नई धारा 10 क जोड़ी गई है।

नोट :

- इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किये गए पंचायतों अथवा उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ऐसा परिसीमन अथवा विभाजन अठारह माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा।
- ऐसी स्थिति में इन पंचायतों और इनके वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन नए सिरे से किया जाएगा।
- प्रदेश में वर्ष 2020 के पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिये सितंबर 2019 में परिसीमन की कार्यवाही की गई थी, जो इस अध्यादेश के परिणामस्वरूप निरस्त हो गई है।
- अब पंचायतों और उनके वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और विभाजन की कार्यवाही पुन: की जाएगी, जिसके आधार पर निर्वाचन की लंबित प्रक्रिया संपन्न होगी।

दृष्टि The Vision

नोट :